साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 25 सितंबर-01 अक्टूबर 2023 वर्ष-9, अंक-24
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

15 अगस्त सरकार ने तय की थी डेड लाइन, डिजिटल पेमेंट पर एक्शन की रफ्तार धीमी

मध्यप्रदेश की पंचायतों में क्यूआर कोड व्यवस्था फ्लॉप

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश की 23000 पंचायत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार की फैसले पर पंचायत और ग्रामीण विकास की चाल धीमी है केंद्र सरकार ने इस मामले में 15 अगस्त तक सभी पंचायत से क्यूआर कोड डेवलप किए जाने और उसके माध्यम से भुगतान करने की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई है इस कारण से प्रदेश की पंचायत में अपेक्षा के अनुरूप डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है हालांकि इस मामले में पंचायत और ग्रामीण विकास के अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है। केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर 15 अगस्त, 2023 तक राज्य की प्रत्येक पंचायत में डिजिटल भुगतान, खास तौर पर राजस्व संग्रह शुरू करने और इसे समारोह के रूप में घोषित करने के लिए कहा था। पंचायतीराज मंत्रालय के संयुक्त सचिव आलोक प्रेम नागर की ओर से सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिखा गया था। इसमें कहा गया है कि अपने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों, ब्लाक पंचायतों और जिला पंचायतों में यूपीआइ से भुगतान की सुविधा शुरू कराएं।

केंद्र ने सेवा प्रदाताओं के नाम भी सुझाए थे

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से डिजिटल भुगतान से जुड़े सेवा प्रदाताओं के नाम भी उपलब्ध कराए थे। इसमें कहा गया कि इनके साथ बैठक कर नियम और निर्देशों के अनुसार चयन कर लें। इसके बाद पंचायत भवनों में क्यूआर कोड लगवा दिए जाएं। ग्रामीणों के जनधन खातों को भी यूपीआइ से लिंक कराया जाए, ताकि वह डिजिटल भुगतान कर सकें लेकिन एमपी में इस पर अभी काफी विलंब की स्थिति है।

लेन देन में भी डिजिटल पेमेंट | केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले में पंचायतों में जेम पोर्टल के माध्यम से होने वाली लेनदेन की प्रक्रिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पंचायत को निर्देश दिए गए हैं कि वह यूपीआई ट्रांजेक्शन वाले डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड विकसित करें और उसके माध्यम से पंचायत द्वारा वसूले जाने टैक्स का भुगतान कराएं।

मप्र में नहीं दिखी रुचि | हालांकि मध्य प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग अभी तक इसको लेकर कोई विशेष पहल नहीं कर पाया है। पंचायतों में इसको लेकर 15 अगस्त तक क्रियान्वयन रिपोर्ट मांगने के केंद्र सरकार के फैसले पर भी विभाग गंभीर नहीं है। इसी कारण जो पंचायतें सक्षम हैं, उन्हें छोड़कर बाकी पंचायतों में इसको लेकर प्रक्रिया तेज नहीं हुई है।

अभी नहीं हो रही मॉनिटरिंग

अभी हालात यह हैं कि पंचायतों में जो टैक्स लगते हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती और टैक्स की पूरी राशि बकायादारों से जमा नहीं कराई जाती है। इससे पंचायतों के क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार की योजनाओं पर पंचायतों को आश्रित रहना पड़ता है। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की स्थिति में पंचायतें अपने अधो संरचना विकास के लिए खुद फंड इकट्ठा कर विकास कार्य करा सकेंगी।

टैक्स कलेक्शन में आएगी पारदर्शिता

केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में डिजिटल पेमेंट के बढ़ावा देने का निर्णय टैक्स कलेक्शन में बढ़ावा देने के लिए मजबूत कदम बताया जा रहा है। अफसरों का मानना है कि यह सिस्टम राज्य में लागू होने के बाद पंचायतों का टैक्स कलेक्शन तो बढ़ेगा ही, टैक्स के पेमेंट में भी पारदर्शिता आएगी। टैक्स कलेक्शन और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों को सौंपी गई है जिसकी मॉनिटरिंग जनपद पंचायतों के सीईओ द्वारा की जाएगी।

सीएम ने फॉर्म भराकर शुरू किया पंजीयन, हरदा की नमिता बनी पहली हितग्राही

'कृषक मित्र' के तहत पंप लगाने पर मिलेगा 50 फीसदी अनुदान

- सरकार 40 और विद्युत कंपनी देगी 10 प्रतिशत सब्सिडी
- शरबती गेहूं, चिन्नोर चावल को मिली ग्लोबल पहचान
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना तत्काल आरंभ होगी
- किसानों ने बनाया मध्यप्रदेश को कृषि में अव्वल
- तीन एचपी या अधिक पंप कनेक्शन के लिए होगा 11केवी लाइन का विस्तार

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में हितग्राहियों से फार्म भरवाने के कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में तीन एचपी या अधिक क्षमता के स्थाई पंप कनेक्शन के लिए 200 मीटर तक की दूरी की 11केवी लाइन के विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना और निम्न दाब लाइन केबल विस्तार कार्य शामिल हैं। योजना में समस्त सामग्री सहित विस्तार कार्य और इसका संधारण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस कार्य का 50 प्रतिशत व्यय शासन द्वारा और 50 प्रतिशत कृषक या कृषक समूह द्वारा वहन किया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में हुए राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जिले के ग्राम जिनवानिया की नमिता रनवे और भैंरूदा सीहोर के प्रेमनारायण पंवार के आवेदन भरवाकर योजना में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ की। सीएम ने कहा कि योजना का क्रियान्वयन तत्काल आरंभ किया जा रहा है।

अन्नदाता हमारे प्राणदाता

मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान हमारे अन्नदाता के साथ-साथ हमारे प्राणदाता भी हैं। वे यदि खेतों में ना खपें तो हमारा जीवन दो-चार दिन भी नहीं चल पाएगा। किसानों की मेहनत, त्याग और तपस्या ने ही मप्र को कृषि क्षेत्र में देश में अव्वल बनाया है। हमारे शरबती गेहूं, चिन्नोर चावल को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रही है। प्रदेश में 2002-03 में खाद्यान्न उत्पादन 159 लाख मैट्रिक टन था, जो अब बढ़कर 619 लाख मैट्रिक टन हो गया है।

0 फीसदी ब्याज पर ऋण

सरकार ने किसानों के लिए 0 फीसदी ब्याज पर ऋण के साथ-साथ पर्याप्त बिजली और सिंचाई की व्यवस्था की है। हर किसान को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है। केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति प्राप्त हो गई है, इससे प्रदेश में सिंचाई का रकबा और बढ़ेगा। सरकार किसान कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वर्षा से यदि कहीं नुकसान हुआ है तो किसान चिंता ना करें, उन्हें सर्वे करा कर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के प्रावधान

- अधोसंरचना विस्तार कार्य एवं सामग्री की व्यवस्था विद्युत कंपनी करेगी।
- अधोसंरचना विकास के खर्च का 50 फीसदी किसानों को देना पड़ेगा।
- 50 फीसदी खर्च राज्य सरकार/ बिजली वितरण कंपनी अदा करेगी।
- पंप कनेक्शन में लाइन, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस बिजली कंपनी करेगी।
- किसानों के समूह आवेदन करेंगे तो सभी को समानुपातिक खर्च उठाना पड़ेगा।
- योजना के तहत किसानों को केवल 50 फीसदी ही राशि भरना पड़ेगी।
- ट्रांसफार्मर व अन्य सामग्री की बेहतर गुणवत्ता से निर्बाध बिजली।
- समस्त रख-रखाव संबंधी कार्य अब बिजली वितरण कंपनी करेगी।
- मध्यप्रदेश में योजना लागू होने से दो साल तक प्रभावशील रहेगी।
- योजना के तहत प्रथम वर्ष दस हजार किसानों को लाभ होगा।

हर खेत को पानी देंगे एक जमाना था जब केवल तीन से चार घंटे बिजली मिलती थी। एक जमाना था जब फसलें खेत में सूखतीं थीं। प्रदेश में बिजली का कुल उत्पादन मात्र 2900 मेगावाट था। आज प्रदेश में 29 हजार मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। सिंचाई क्षमता 7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर हो चुकी है, 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को संचित करना हमारा लक्ष्य है। हम अपने संकल्प के अनुरूप हर खेत को पानी देंगे।

स्व-सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिलाएगा प्रशासन

मशरूम की खेती देगी एसएसजी को मजबूती, समूहों की सुधरेगी सेहत

जबलपुर। जागत गांव हमार

देसी गोश्त कहे जाने वाले मशरूम की खेती बड़े लाभ का धंधा है। इसमें जगह तो बहुत कम लगती है, लेकिन फसल की देखभाल बहुत ज्यादा करना पड़ती है। दिनों की गिनती कर मशरूम की उपज की मानीटरिंग करना पड़ता है। सप्लाई और फसल तैयार होने के गणित से ही बैग तैयार कर उनमें बीज लगाए जाते हैं। ढाई सौ वर्ग फुट के अंधेरे या कम रोशनी वाले कमरे में होने वाली इस खेती में प्रबंधन इतना ज्यादा करना पड़ता है कि आम किसान इस फसल को लेने खुद को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाता। स्व सहायता समूहों में 10 या इससे अधिक सदस्य होते हैं, जो एकजुट होकर मशरूम की खेती को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसलिए जिला पंचायत ने जिले के स्व सहायता समूहों के 42 परिवारों से मशरूम की खेती कराने की योजना बनाई है।

42 यूनिटों से मशरूम की खेती कराएंगे- मशरूम का उत्पादन किसानों के लिए अत्यंत लाभदाई है। इसे प्रोत्साहित करने जिला पंचायत प्रशासन के एसआरएलएम (राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उसके द्वारा आदिवासी बाहुल्य कुंडम विकासखंड में स्व-सहायता समूहों से जुड़ी 42 यूनिटों से मशरूम की खेती कराने की तैयारी है। इन सभी एसएसजी यूनिटों को सौ-सौ प्रोडक्शन बैग और मशरूम बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पूर्व उन्हें बकायदा मशरूम की खेती के लिए सामान्य प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इस योजना से जहां स्व-सहायता समूह के सदस्यों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, वहीं इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन से भी हरी झंडी मिल चुकी है।

लगात और आवक का लेखा-जोखा

इस खेती में जगह और लागत बहुत अधिक नहीं लगती। ढाई सौ वर्ग फुट के कमरे में इसकी खेती की जा सकती है। लागत की बात करें तो 3000 रुपये का बीज, 4000 हजार रुपए का गेहूं का भूसा-लकड़ी का बुरादा और जिप्सम, 3000 का लेबर चार्ज, 2000 रुपए सिंचाई और 2000 रुपए कैमिकल एवं फर्टीलाइजर के लिए लगना हैं, इतने में 200 बैग तैयार हो जाएंगे। प्रत्येक बैग में 22 से 25 दिन में एक किलो मशरूम पैदा हो सकता है। बाजार में फ्रेश मशरूम 150 रुपए किलो बिकता है। इस तरह से एक यूनिट एक महीने से भी कम समय में 14 हजार रुपए की लागत में इतना ही मुनाफा अर्जित कर सकती है।

चाहें तो बढ़ा सकते हैं बैगों की संख्या

स्व सहायता समूह जगह और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार बैगों की संख्या बढ़ा सकते हैं। वे जितने अधिक बैग इस्तेमाल करेंगे और जितनी ज्यादा सप्लाई कर पाने में सफल रहेंगे, उतना अधिक लाभ अर्जित करने की स्थिति में रहेंगे। खास बात यह है कि एक बार तैयार बैग कम से कम तीन बार उपयोग में लाया जा सकता है। यानि उसमें केवल बीज और फर्टीलाइजर डालने की ही जरूरत रहेगी।

स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने उनको मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुंडम के 42 एसएसजी परिवारों से मशरूम की खेती कराने के प्रस्ताव को कलेक्टर से हरी झंडी मिल चुकी है।
-मनोज सिंह, एसीइओ-जिला पंचायत, जबलपुर

सोयाबीन का उत्पादन 149 लाख टन से ज्यादा

सोपा ने जारी की रिपोर्टः सोयाबीन के अच्छे उत्पादन की उम्मीद

भोपाल। जागत गांव हमार

मौसम की बदली परस्थितियों और अनूकूल बरसात के कारण सोयाबीन के उत्पादन की स्थिति भी इस साल बेहतर हो रही है। लंबी खेंच के बाद एन वक्त पर हुई झमाझम वर्षा ने सोयाबीन की फसल में जान फूंक दी है। दि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सोपा) ने ताजा सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार इस तेल वर्ष यानी अक्टूबर-2022 से सितंबर-2023 के बीच सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के साथ सोयामील के निर्यात का आंकड़ा भी ऊपर की ओर जा रहा है। सोपा द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस साल देशभर की फसल की स्थिति को देखकर सोयाबीन का उत्पादन कुल 124.11 लाख टन आंका गया है। इसमें बीते वर्ष का कैरीफारवर्ड स्टाक भी जोड़ लिया जाए तो फसल का कुल आंकड़ा 149.26 लाख टन तक पहुंच रहा है। बोवनी के लिए किसान सोयाबीन हाथ में रखेंगे इसके बाद भी 143 लाख टन से ज्यादा सोयाबीन क्रशिंग के लिए उपलब्ध है। सोपा के अनुसार, अगस्त तक मंडियों में 112 लाख टन सोयाबीन पहुंच चुका है।

सोयामील का घरेलू उपभोग भी बढ़ा है

सोपा की रिपोर्ट के अनुसार तेल वर्ष 2022-2023 जो अक्टूबर-2022 से शुरू होकर सितंबर-2023 तक चलेगा। इसमें सोयाबीन निर्यात 7 लाख टन हो गया है। बीते साल के 5.5 लाख टन से बढ़कर। इसी तरह सोयामील का निर्यात भी 18 लाख टन हो गया है। बीते वर्ष 17.5 लाख टन था। इसी तरह सोयामील का घरेलू उपभोग भी बढ़ा है। सोयाबीन क्रशिंग 106.50 लाख टन है। जो डेढ़ लाख टन ज्यादा है बीते वर्ष के मुकाबले। बीते दिनों की बरसात के कारण फसलों की स्थिति मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र में भी बेहतर हुई है। अक्टूबर से देशभर की मंडियों में नई फसल की आवक की उम्मीद की जा रही है। सोयाबीन की स्थिति को देखते हुए खाद्य तेल के दाम भी नियंत्रित दायरे में बने रहने के आसार हैं।

प्रबंधन ने 150 पदों को भरने की शुरू की कवायद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सहमति मिल गई

जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि में भरे जाएंगे गैर तकनीक पद

जबलपुर। जागत गांव हमार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षा, शोध और प्रसार से जुड़े कामों को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए विवि के लगभग डेढ़ सौ से ज्यादा रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसमें तकनीक और गैर तकनीक पद शामिल हैं। इन पदों को भरकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले नए कृषि विज्ञान केंद्र और नए कालेजों के काम की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। पहले चरण में कृषि विज्ञान केंद्र के पद भरने हैं। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सहमति मिल गई है और तकनीक और गैर तकनीक के लगभग 150 से 165 पदों को भर जाएगा। इसमें तकनीक पद लगभग 50 हैं।

विवि प्रशासन किसी तरह का विवाद नहीं चाहता- जनेकृविवि प्रशासन तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने का जिम्मा खुद नहीं उठाएगा, बल्कि यह जिम्मेदारी वह प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को देने जा रहा है। इसकी पीछे की वजह तृतीय श्रेणी के पदों के लिए आने वाले आवेदन और प्रक्रिया है। इसको लेकर विवि प्रशासन किसी तरह का विवाद नहीं चाहते, इसलिए वह यह जिम्मेदारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को देने का तय किया है।

नियम और चयन समिति को दी जिम्मेदारी

जनेकृविवि इस साल तीन नए कृषि विज्ञान शुरू करने जा रहा है। इनमें एक देवरी, दूसरा सागर और तीसरा सिंगरौली में हो रहा है। इनमें लगभग 48 पद हैं। इन पदों को भरने की परमिशन आइसीएआर ने दी है। इसके बाद विवि ने तकनीक पदों को भरने के लिए कमेटियां बना दी हैं। कमेटी इन दिनों केविके के तय पदों के आधार पर रोस्टर तैयार कर रही है। पिछले कई दिनों से इसको लेकर विवि, एक्सपर्ट की मदद से इस काम को पूरा करने में जुटा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। हालांकि रोस्टर बनाने के लिए विवि अहतियात बरत रहा है, ताकि भर्ती में किसी तरह की परेशानी न हो। यही वजह है कि उसने इसके लिए अनुभवियों के साथ कानूनी सलाहकारों की मदद ली है।

यह पद हैं खाली

कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालय में तकनीक और गैर तकनीकी के सैकड़ों पद सालों से खाली हैं। तृतीय श्रेणी के पदों को विवि के पिछले दस साल ने खुद नहीं भरा है। उसने यह जिम्मेदारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को दी है। इनमें ड्राइवर और क्लर्क के पद हैं। वहीं चतुर्थ श्रेणी के चपरासी के पद हैं। इन पदों को भरने की कवायद विवि को ही करना होगा। इधर तीन केविके में अभी सीनियर साइंटिस्ट, एसएमएस और टीए के पद भरे जा रहे हैं। यह पद विवि खुद भरेगा। इसके लिए विज्ञापन जारी कर जल्द ही वह आवेदन मांगवाएगा और फिर स्कोर कार्ड तैयार कर उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। हालांकि इस बीच आचार संहिता का पेंच भी आड़े आ रहा है। इसे देखते हुए विवि ने अपनी तैयारियों की रफ्तार बढ़ा दी है।

अभी तक यह काम

- भर्ती प्रक्रिया के लिए कमेटी बना दी है, जिसका चेयरमेन डायरेक्टर एक्सटेंशन को बनाया गया है।
- रिक्त पदों के आधार पर रोस्टर बनाने का काम पूरा हो गया है, इस पर अंतिम सहमति होना है।
- जल्द ही विज्ञापन जारी होंगे, इसके बाद आवेदन मांगे जाएंगे और फिर साक्षात्कार होंगे।
- पद और उसकी योग्यता में भी इस बार आइसीएआर ने कई बड़े बदलाव किए हैं।

विवि और कृषि विज्ञान केंद्र में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। सभी पहलुओं का नियमानुसार अध्ययन करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
प्रो.पीके मिश्रा, कुलपति जनेकृविवि

-मप्र सरकार ने अलग से बांस-बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया

बांस की खेती के लिए किसान को प्रति पौधा मिलेगा 120 रुपए तक अनुदान

सरकार ही खरीदेगी: हरा सोना बढ़ाएगा धन-धान्य, हमारा पर्यावरण भी इससे सुधरेगा

ग्वालियर। जागत गांव हमार

बांस का मानव जीवन से अटूट रिश्ता है। यह व्यक्ति के जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक में साथ देता है। इसलिए बांस का उल्लेख हमारे धर्मग्रंथों में भी है। इसके जलाने पर धर्मानुसार पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि बांस प्रकृति का सबसे सुंदर पौधा है जो हमारे वायुमंडल को स्वच्छ रखने के कार्य के साथ समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए राज्य से लेकर केन्द्र सरकार बांस की खेती पर जोर दे रही है। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अलग से बांस व बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन तक किया है। बांस को हरा सोना कहा जाता है, क्योंकि यह किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ने के साथ शिल्पियों को रोजगार देने का काम कर रहा है। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बांस का उपयोग बढ़ रहा है। बास वायुमंडल से सर्वाधिक कार्बनडाइआक्साइड को अवशोषित करने वाला पौधा है। इसलिए प्रतिवर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है।

बांस की खेती पर सरकार से अनुदान- बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम पिरोनिया बताते हैं कि बांस की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बांस का एक पौधा तैयार होने में तीन साल का वक्त लगता है। एक पौधे को तैयार करने के लिए शासन किसान को 120 रुपए का अनुदान देगी, जिसके लिए किसान को बांस की खेती करने के लिए वन विभाग में आवेदन करना होगा। वन विभाग आपको पौध देगी, लगवाने में भी मदद करेगा और जब पौधा, पेड़ बन जाएगा तो उसे खरीदने का काम भी वन विभाग करेगा।

बांस का मानव जीवन से रिश्ता

बांस का मनुष्य जीवन के साथ अटूट रिश्ता है। मनुष्य के कई प्रमुख संस्कारों में बांस की जरूरत पड़ती है। शादी का मंडप हो या मुंडन संस्कार, यहां तक कि अंतिम संस्कार में भी बांस ही हमें सहारा देता है। बांस एक ऐसा कुदरती उपहार है, जिसकी चर्चा धर्मग्रंथों में भी है। इसे लेकर अनेक मान्यताएं और लोक कथाएं व लोक मुहावरे प्रचलित हैं। इतना ही नहीं वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में भी बांस को लेकर कई तरह की बातें कही गई हैं। कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। दरअसल, इन दिनों घरों और कार्यालयों में बांस का पौधा लगाने का चलन भी बढ़ गया है। बांस घर व कार्यालय में शांति व सकारात्मक उर्जा का संचार करने वाला बताया गया है। इससे आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। यह हमें नकारात्मक स्थिति से बचाता है और रिश्तों में मजबूती लाता है।

बांस से सोफा, पानी की बोतल

बांस पर्यावरण की रक्षा करने का सर्वोत्तम विकल्प है। बांस से कप, प्लेट, पत्तल, बोतल, लैंप, गिलास, थैला, डलिया, बाल्टी, मग, हर वह सामान तैयार होता है, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। इससे प्लास्टिक से तैयार होने वाले सामान की बिक्री रुकेगी, जिससे पर्यावरण की रक्षा होगी। इसके अलावा सोफा, कुर्सी, टेबल, झूला, सब बांस का तैयार होता है। अब बांस के बैरिकेड तक बनने लगे हैं, जिनका उपयोग कई राज्यों में यातायात पुलिस कर रही है।

सनातन धर्म में बांस जलाना मना

सानतन धर्म में बांस के सबसे ज्यादा महत्व का उल्लेख मिलता है। हमारे धर्मग्रंथों की मानें तो बांस को नहीं जलाना चाहिए। बांस का हवन-पूजन में इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। यह मान्यता है कि बांस जलाने वालों के वंश का नाश होता है। यही नहीं धार्मिक मान्यता है कि बांस जलाने से पितृदोष भी लगता है। एक तर्क यह भी दिया है कि भगवान श्रीकृष्ण हमेशा बांसुरी बजाया करते थे, इसलिए भी बांस नहीं जलाना चाहिए। इसके अलावा बांस का प्रयोग सभी तरह के संस्कारों में किया जाता है। मान्यता है कि बांस का पौधा जहां होता है, वहां कभी बुरी आत्मा नहीं होती है।

विज्ञान भी धर्मशास्त्र के विचारों की करता है पुष्टि

बांस क्यों नहीं जलाना चाहिए, इसे लेकर धर्मशास्त्र अपनी तरह से व्याख्या करते हैं, उसके पास अपने तर्क हैं, लेकिन हैरानी की बात यह कि विज्ञान भी इससे सहमत है कि बांस को नहीं जलाना चाहिए। इसके पीछे विज्ञान का तर्क है कि बांस में लेड, क्रोमियम, कापर व भारी धातुएं मौजूद होती हैं। जैसे ही इसे जलाया जाता है तो इससे जहरीली गैस निकलने लगती है। इससे वातावरण दूषित हो जाता है सांस संबंधी बीमारियों के साथ साथ यह जानलेवा हो सकता है।

-आयसर के वैज्ञानिकों ने औषधीय गुणों से युक्त ड्राफ्ट जीनोम का पता लगाया

वैज्ञानिकों ने औषधीय गुणों से युक्त ड्राफ्ट जीनोम का पता लगाया

आंवले की नई किस्म विकसित करने की राह आसान, अब बढ़ेगी गुणवत्ता

भोपाल। जागत गांव हमार

राजधानी में स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने पहली बार आंवला पौधे के ड्राफ्ट जीनोम का पता लगाया है। इससे आंवले की जीनोमिक संरचना को समझने से उसकी उत्पत्ति, विकास और औषधीय महत्व वाले जैव रसायन कैसे बन सकते हैं, इन सबके बारे में समझने में मदद मिलेगी। शोध दल ने अपने अध्ययन में पाया कि विटामिन-सी, फ्लेवोनोइड और लिगनिन बायोसिंथेसिस से संबंधित जीन आंवले में विकसित हुए। यह जीनोमिक संसाधन कृषकों को बढ़े हुए विटामिन-सी और औषधीय गुणों वाली बेहतर किस्मों को विकसित करने में मदद देंगे। यह शोध जैविक विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विनीत शर्मा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें श्रुति महाजन, मनोहर सिंह बिष्ट और अभिषेक चक्रवर्ती ने भी सहयोग प्रदान किया।

इलाज में प्रभावी - आंवला को अनियमित फैट स्तर, टाइप 2 डायबिटीज, मसूड़ों की बीमारियों, गठियावात और अन्य बीमारियों के इलाज में प्रभावी माना गया है। इसके अतिरिक्त

आंवले में पोषण संबंधी महत्वपूर्ण गुण होते हैं, किंतु अभी तक इसकी आनुवांशिक संरचना का विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया था।

विटामिन सी की मात्रा ज्यादा

आंवला दक्षिण एशियाई देशों में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध पौधा है। इसका उपयोग सदियों से पारंपरिक भारतीय और चीनी चिकित्सा और घरेलू उपचार में किया जाता रहा है। आंवले के गुठलीदार फल में विटामिन सी की मात्रा काफी अधिक होती है। इसके अलावा यह विभिन्न फाइटोकेमिकल्स, खनिज और अमीनो एसिड का एक समृद्ध स्रोत है।

इन चीजों में मिलेगी मदद

इस शोध में टीम ने पाया कि आंवले की असाधारण प्रतिरोधक क्षमता उन जीनों के सहायक विकास से आती है, जो एंटीआक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी और फ्लेवोनायड के उत्पादन में शामिल होते हैं। इस शोध से विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत को सिंथेटिक स्रोत में बदलने में मदद मिलेगी। 26 अन्य पौधों की प्रजातियों से आंवला की तुलना के बाद हमारे द्वारा इसके संपूर्ण जीनोमिक परिदृश्य का विश्लेषण किया गया। इसके बाद हमें आंवला के विकासवादी वंश को समझने में भी मदद मिली है। यह शोध बेहतर पोषण, भोजन, सौंदर्य प्रसाधन और औषधीय उत्पादों को विकसित करने के साथ ही बागवानी और जीनोमिक अध्ययन में भी मदद करेगा।

इस तकनीकी दृष्टिकोण के बारे में समझाते हुए कहा कि हमने इसके पौधे की पत्तियों का उपयोग करके आंवले के जीनोम और ट्रांसक्रिप्टोम सीक्वेंसिंग का विश्लेषण किया है। हमने विटामिन सी की उत्पादन के लिए जिम्मेदार जींस की भी पहचान की है और इसकी तुलना विटामिन सी से युक्त फल देने वाले अन्य पौधों के जींस से की है।

डॉ. विनीत शर्मा, प्रमुख शोधकर्ता, आईआईएसईआर

परियोजना 22 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का सशक्त माध्यम बनी

रतलाम के कोटेश्वर तालाब से लाभांवित हो रहे ढाई हजार किसान

भोपाल। जागत गांव हमार

रतलाम जिले की पहली फव्वारा पद्धति से बनी कोटेश्वर इमलीपाड़ा सिंचाई तालाब परियोजना से 2354 किसान परिवार लाभांवित हो रहे हैं। यह महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना लगभग 22 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का सशक्त माध्यम बनी है। कोटेश्वर तालाब का निर्माण राज्य शासन द्वारा 69 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। इस तालाब का लाभ रतलाम तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के करीब 13 गांव के लोगों को मिल रहा है। यह परियोजना इमलीपाड़ा गाँव के अलावा मुख्य रूप से रावलिया, खेड़ा-खेड़ी, पीपलोदी, बावड़ीखेड़ा, पीपलखूंटा, उमरन, पिपलीपाड़ा, बसंतपुरा, कुण्डालपाड़ा एवं गुजरपाड़ा के 2354 किसान परिवारों के लिये वरदान बनी है। तालाब निर्माण के पहले यहां के किसान परम्परागत खेती किया करते थे। तालाब बन जाने के बाद अब किसान परम्परागत फसलों के साथ-साथ अमरूद, नींबू और पपीता जैसी उद्यानिकी फसल लेने में सक्षम हो गये हैं। इस क्षेत्र में उद्यानिकी खेती के रकबे में भी अच्छी-खासी वृद्धि हुई है।

भू-जल स्तर में भी वृद्धि

भू-जल स्तर में भी वृद्धि हुई है। मछली-पालन के साथ अब मवेशियों को पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। प्रेशराइज्ड सिंचाई प्रणाली से पानी की खपत कम होती है और किसानों के पास ज्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है। कोटेश्वर सिंचाई तालाब की अधिकतम ऊंचाई 23.25 मीटर है। तालाब की कुल जल-भराव क्षमता 10 घन मीटर की है।

भू-क्षरण की भेंट चढ़ चुकी है 42 करोड़ हैक्टेयर उपजाऊ जमीन

यूएनसीसीडी की मानें तो 2015 से 2019 के बीच हर साल कम से कम 10 करोड़ हेक्टेयर स्वास्थ्य और उत्पादक जमीन खराब हो रही थी। कुल मिलकर देखें तो अब तक 42 करोड़ हेक्टयर जमीन बर्बाद हो चुकी है, जो क्षेत्रफल में पांच मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के कुल आकार से थोड़ा अधिक है।नुकसान की मौजूदा दर के लिहाज से देखें तो दुनिया को भू-क्षरण से मुक्त कराने के लिए 2030 तक 150 करोड़ हेक्टेयर जमीन को बहाल करने की आवश्यकता होगी। यह जानकारी भूमि संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े संगठन यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों में सामने आई है।

मध्य एशिया के आकार की जितनी जमीन जो कभी स्वास्थ्य और उत्पादक थी, वो 2015 के बाद से अपनी गुणवत्ता खो चुकी है। इसकी वजह से दुनिया भर में भोजन-पानी की समस्या पैदा हो गई है, जो सीधे तौर पर 130 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है।

यह जानकारी भूमि संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े संगठन यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों में सामने आई है।

यूएनसीसीडी की मानें तो 2015 से 2019 के बीच हर साल कम से कम 10 करोड़ हेक्टेयर स्वास्थ्य और उत्पादक जमीन खराब हो रही थी। कुल मिलकर देखें तो अब तक 42 करोड़ हेक्टयर जमीन बर्बाद हो चुकी है, जो क्षेत्रफल में पांच मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के कुल आकार से थोड़ा अधिक है।

यूएनसीसीडी ने अपने बयान में कहा है कि, यदि भूमि की गुणवत्ता में आती गिरावट का यह रुझान जारी रहता है तो इससे निपटने के लिए 2030 तक 150 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बहाल करने की आवश्यकता होगी। इसका वैकल्पिक उपाय यह है कि और अधिक भूमि को खराब होने से रोका जाए, साथ ही 100 करोड़ हेक्टेयर जमीन को बहाल करने का जो संकल्प लिया गया है उसपर तेजी से काम किया जाए। इसकी मदद से नुकसान को रोकने का जो लक्ष्य रखा गया है उससे ज्यादा हासिल किया जा सकता है।

2017 में, हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप-13) के 13वें सत्र में यूएनसीसीडी ने भूमि संरक्षण के लिए 2018-2030 के रणनीतिक ढांचे को अपनाया था। साथ ही इस दौरान यूएनसीसीडी ने देशों को मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से जुड़ी अपनी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और प्रक्रियाओं में इस फ्रेमवर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया था।

गौरतलब है कि इस साल के अंत में पार्टियां यह आंकलन करेंगी कि फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को कितनी अच्छी तरह क्रियान्वित किया गया है। इसके लिए सभी पक्ष 13 से 17 नवंबर, 2023 के बीच उज्बेकिस्तान के समरकंद में कन्वेंशन के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बनाई समिति (सीआरआईसी 21) के 21वें सत्र में एकजुट होंगी।

इस बारे में सीआरआईसी 21, जोकि यूएनसीसीडी की

एक आधिकारिक बैठक है, वो यह जांच करेगी कि इन मुद्दों पर कितनी बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है-

शाश्वत भूमि प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

सूखे से बेहतर तरीके से निपटना।

शाश्वत कृषि में महिलाओं के नेतृत्व का समर्थन करना

जलवायु परिवर्तन और भूमि की गुणवत्ता में आती गिरावट के चलते घर छोड़ने वालों की समस्याओं को हल करना।

यह बैठक भूमि की गुणवत्ता में आती गिरावट के साथ-साथ सूखे से जुड़े नवीनतम वैश्विक रुझानों को भी उजागर करेगी। साथ ही इसकी भी समीक्षा करेगी कि देश भूमि की बहाली के मुद्दे पर कैसे प्रगति कर रहे हैं। यह पहला मौका है जब यूएनसीसीडी की बैठक मध्य एशिया में होगी।

भूमि की गुणवत्ता में आती गिरावट एक तरफ जहां जलवायु में आते बदलावों और मौसमी घटनाओं में योगदान दे रहीं है वहीं दूसरी और इससे प्रभावित भी हो रही है। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया पहले से कहीं ज्यादा चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर रही है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पड़ती भीषण गर्मी और जंगल में लगी आग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बार-बार फेल होता मानसून, एशिया में आती विनाशकारी बाढ़, बारिश और चक्रवात कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जिनमें लगातार वृद्धि हो रही है।

इस फ्रेमवर्क में पांच महत्वपूर्ण लक्ष्य शामिल हैं, जो 2018 से 2030 के बीच यूएनसीसीडी से जुड़े सभी लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए हैं।

प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना, मरुस्थलीकरण/भूमि क्षरण से निपटना, स्थाई भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना। भूमि क्षरण को रोकने में मदद करना। प्रभावित लोगों के जीवन को बेहतर बनाना।

कमजोर आबादी और पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक लचीला बनाने में मदद करने के लिए सूखे के प्रभावों से निपटना और प्रबंधित करना। यूएनसीसीडी के प्रभावी कार्यान्वयन से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को लाभ पहुंचाना। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत साझेदारियां बनाना, जिससे कन्वेंशन के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त फण्ड और संसाधन इकट्ठा करना।

ऐसे में यूएनसीसीडी के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाव का कहना है कि, हमें तत्काल और अधिक भूमि को बर्बाद होने से रोकना होगा। 2030 तक भूमि के लिए तय वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कम से कम 100 करोड़ हेक्टेयर भूमि की बहाली के लिए शीघ्रता से प्रयास करने की आवश्यकता है।

सरसों की उन्नत जैविक खेती और उसके लाभ

» डॉ. कीर्ति शर्मा
सीनियर रिसर्च फेलो, सस्य विज्ञान विभाग, गोविंद बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
» डॉ. विशाल मेहता, सहायक प्राध्यापक, कृषि सांख्यिकी विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज-, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।

देश में क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों की दृष्टि से सरसों का तिलहन फसलों में प्रमुख स्थान है। सरसों रबी की एक प्रमुख तिलहनी फसल है। जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विशेष स्थान है। इसकी खेती मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में की जाती है। सरसों कृषकों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इससें कम सिंचाई व लागत में दूसरी फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इसकी खेती मिश्रित रूप से एवं दो फसलीय चक्र में आसानी से की जा सकती है। अकेले राजस्थान में देश का सबसे बड़ा हिस्से में सरसों की पैदावार होती है।

सरसों के तेल में न्यूनतम वसा, अम्ल तथा लिनोलनिक तथा लिकोनिक अम्ल की मौजूदगी इसके लाभकारी गुणों को प्रदर्शित करती है। परंतु इसके तेल में इरूसिक अम्ल की अधिक मात्रा अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मे पिछले कुछ वर्षों से सरसों की जैविक खेती पर शोध कार्य प्रारंभ किया गया। इस शोध कार्य में पोषण प्रबंधन, उन्नत सस्य तकनीक तथा कीट एवं बीमारियों की रोकथाम का विशेष ध्यान रखा गया। इस शोध से यह स्पष्ट हो गया है कि जैविक पद्धति द्वारा सरसों की भरपूर उपज प्राप्त की जा सकती है।

जैविक सरसों उत्पादन से लाभ: मृदा में जैविक कार्बन एवं उर्वरता में सुधार होता है। मृदा में होने वाली जैविक क्रियाओं में सुधार होता है। जैविक खादों तथा कीटों व बीमारियों की रोकथाम में काम आने वाले पदार्थों का उत्पादन किसान अपने खेत पर ही कर सकते है, जिससे उत्पादन लागत में कमी हो जाती है।

जैविक कृषि में कचरे के उचित प्रबंधन द्वारा प्राकृतिक संतुलन बना रहता है तथा साथ ही पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आती है। मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में सुधार होता है। सरसों की पत्तियां सूखकर झड़कर खेत की मिट्टी में मिल जाती हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देती हैं। मृदा में उपस्थित विभिन्न लाभदायक जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है।

सिंचित क्षेत्र की किस्में:				
किस्में	पकाव अवधि	उपज(किग्रा/है.)	तेल (%)	पैदावर के लिए उपयुक्त क्षेत्र
पूसा बोल्ड	110-140	2000-2500	40	राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र
पूसा जयकिसान (बायो 902)	155-135	2500-3500	40	गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र
क्रान्ति	125-135	1100-2135	42	हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान
आर एच 30	130-135	1600-2200	39	हरियाणा, पंजाब, पश्चिम राजस्थान
आर एल एम 619	140-145	1340-1900	42	गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर,
असिंचित क्षेत्र की किस्में:				
अरावली	130-135	1200-1500	42	राजस्थान, हरियाणा
गीता	145-150	1700-1800	40	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
आर जी एन 48	138-157	1600-2000	40	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
आर बी 50	141-152	846-2425	40	दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान
पूसा बहार	108-110	1000-1200	42	असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल
अगेती बुआई तथा कम समय में पकने वाली किस्में:				
पूसा अग्रणी	110-115	500-1800	40	दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान
पूसा मस्टर्ड 27	115-120	1400-1700	42	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड
पूसा मस्टर्ड 28	105-110	1750-1990	41.5	हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली
पूसा सरसों 25	105-110		39.6	उत्तरी पश्चिमी राज्य
पूसा तारक	118-123	-	40	उत्तरी पश्चिमी राज्य
पूसा महक	115-120	-	40	उत्तरी-पूर्वी व पूर्वी राज्य

सरसों की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु: भारत में सरसों की खेती शीत ऋतु में की जाती है। इस फसल को 18 से 25 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। सरसों की फसल के लिए फूल आते समय वर्षा, अधिक आर्द्रता एवं वायुमण्डल में बादल छायें रहना अच्छा नही रहता है। अगर इस प्रकार का मौसम होता है, तो फसल पर माहू या चैप के आने की अधिक संभावना हो जाती है।

भूमि का चयन: सरसों समतल और अच्छे जल निकासी वाली बलुई और दोमट मिट्टी में अच्छी उपज देती है। इसके लिए जमीन गहरी और इसमें जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पी. एच. मान उदासीन होना चाहिए। अत्यधिक अम्लीय एवं क्षारीय मृदा इसकी खेती हेतु उपयुक्त नहीं है। यद्यपि क्षारीय भूमि में उपयुक्त किस्म लेकर इसकी खेती की जा सकती है। भूमि क्षारीय हो वहां हर तीसरे वर्ष जिप्सम 5 टन/हैक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम की आवश्यकता मृदा पी. एच. मान के अनुसार भिन्न हो सकती है।

विश्व गैंडा दिवसः विलुप्त होने से बचाने का एक सार्थक प्रयास

गैंडा, जिसे कभी-कभी गैंडा भी कहा जाता है, पांच जीवित गैंडा अनगुलेट प्रजातियों में से एक या कई विलुप्त गैंडा प्रजातियों में से एक है। वे अभी भी जीवित सबसे बड़े मेगाफौना में से हैं, जिनमें से प्रत्येक वयस्क का वजन कम से कम एक टन है। लगातार गैंडे के अवैध शिकार के कारण, गैंडे की अधिकांश मौजूदा प्रजातियाँ लुप्तप्राय मानी जाती हैं। शिकारी गैंडों को उनके सींगों के लिए मार देते हैं, जिन्हें बाद में ऊंचे दामों पर काले बाज़ार में खरीदा और बेचा जाता है। हर साल 22 सितंबर को लोग इन अद्भुत जानवरों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयास में विश्व गैंडा दिवस मनाते हैं।

हर साल 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव कोष, दक्षिण अफ्रीका ने गैंडों के संकट और विभिन्न प्रकार के गैंडों को बचाने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व गैंडा दिवस की घोषणा की।

इस वर्ष विश्व गैंडा दिवस शुक्रवार को मनाया जाएगा। विश्व राइनो दिवस 2023 की थीम के लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, हालांकि, 2022 की थीम सार्वभौमिक और सभी आगामी समारोहों के लिए उपयुक्त लगती है।

विश्व गैंडा दिवस का इतिहास: दक्षिण अफ्रीकी वन्यजीव संगठनों ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय गैंडा प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2010 में विश्व गैंडा दिवस मनाया। लिसा जेन कैपबेल नाम की एक महिला ने 2011 में रिशजा (एक अन्य गैंडा प्रेमी) को भेजे एक पत्र में दुनिया भर में रहने वाले कम से कम पांच प्रकार के गैंडों को देखने की इच्छा व्यक्त की। तब से, विश्व गैंडा दिवस हर साल मनाया जाता है। अपने कीमती सींगों के लिए गैंडों के व्यापक अवैध शिकार के परिणामस्वरूप गैंडा संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

विश्व गैंडा दिवस की लोकप्रियता बढ़ी है, जिससे सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को गैंडे के अवैध शिकार और निवास स्थान के विनाश से लड़ने के लिए एक साथ लाया गया है, साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन प्रतिष्ठित जानवरों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है।

विश्व गैंडा दिवस का महत्व: विश्व गैंडा दिवस समर्थन जुटाने, जनता को शिक्षित करने और इन शानदार प्राणियों की रक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कानून-प्रवर्तन गतिविधियों के माध्यम से गैंडों की रक्षा करना, और गैंडा उत्पादों के अवैध शिकार और तस्करी को रोकने और मुकदमा चलाने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण का समर्थन करना। प्राथमिकता वाले गैंडा संरक्षण प्रयासों को निधि देने के लिए स्थायी वित्तपोषण तंत्र और संरचनाओं का पता लगाना और विकसित करना। यह सुनिश्चित करना कि गैंडा संरक्षण पेशेवर उचित रूप से कुशल और प्रशिक्षित हैं। गैंडा रेंज राज्य संरक्षण एजेंसियों और पेशेवरों के भीतर और उनके बीच समन्वय में सुधार करना। मान्यता, प्रक्रिया और वितरण के इक्विटी त्रिकोण के अनुसार राइनो रेंज राज्यों में कई हितधारकों के साथ जुड़ना।

किसानों की सुविधाओं पर सरकार का फोकस, खेती बनेगी लाभ का धंधा

रोटावेटर, रोटोकल्टीवेटर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही सब्सिडी

प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 03 अक्टूबर-2023 को लॉटरी निकाली जाएगी

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने एवं खेती की लागत को कम करने के लिए सरकार कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्र खरीद सकें इसके लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि यंत्र की खरीद पर भारी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को रोटावेटर, श्रेडर/मल्चर, रोटोकल्टीवेटर, चॉफ कटर, रीपर एवं रीपर कम बाइंडर कृषि यंत्र अनुदान पर देने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। जारी लक्ष्यों के विरुद्ध राज्य के किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र का चयन कर 20 सितम्बर-2023 दोपहर 12 बजे से 02 अक्टूबर-2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 03 अक्टूबर-2023 को लॉटरी निकाली जाएगी। जिसके बाद चयनित किसान योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र ले सकते हैं।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने अभी खरीफ फसलों की कटाई एवं रबी फसलों की बुआई के लिए आवश्यक कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। जो इस प्रकार है-

रोटावेटर,श्रेडर/मल्चर, रोटोकल्टीवेटर (35 एचपी से अधिक), चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित), रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित) एवं रीपर कम बाइंडर

कितना अनुदान

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। इसमें किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

किसान आवेदन कहां करें

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अत: जो किसान भाई दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

देना होगा डिमांड ड्राफ्ट डीडी

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (सूचि देखने के लिए क्लिक करें) के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसमें किसानों को कृषि यंत्र रोटावेटर, श्रेडर/मल्चर, रोटोकल्टीवेटर (35 एचपी से अधिक), पावर ऑपरेटेड चैफ कटर, रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित) हेतु राशि 5000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) एवं कृषि यंत्र रीपर कम बाईंडर हेतु राशि 10,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।

चार माह में फसल हो जाती है पककर तैयार

मूंगफली की उन्नत खेती किसानों को कर सकती है मालामाल

भोपाल। जागत गांव हमार

हमारे देश में रहने वाले ज्यादा लोगों को मूंगफली बेहद पसंद है। भारत के कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है। यदि आप भी किसान हैं तो मूंगफली की खेती कर शानदार कमाई कर सकते हैं। इसकी खेती में करीब 4 माह का समय लगता है। ये खेती की सही तकनीक पर भी निर्भर करता है। इसलिए अच्छी कमाई प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि मूंगफली की खेती को उन्नत बीज और आधुनिक तकनीक के साथ किया जाए।

मूंगफली की फसल के लिए खेतों में तीन से चार बार जुताई करें। इसके बाद मिट्टी को समतल करें और फिर समतलीकरण के बाद खेत में जरूरत के हिसाब से जैविक खाद, उर्वरक और पोषक तत्वों का भी प्रयोग करें। जिससे अच्छी उपज मिल सके। खेत तैयारी करने के बाद मूंगफली की बोवनी के बीजों को तैयार करना चाहिए। जिससे बीमारियां और कीड़े फसल में न पनप सकें। बुवाई के लिए उन्नत किस्मों और बीजों का उपयोग करें। इससे फसल बीमारी की संभावना कम होती है। बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 60 से 70 किग्रा बीज दर का इस्तेमाल करें।

जरूरी सिंचाई

मूंगफली की फसल सिर्फ बारिश पर निर्भर करती है, इसलिए इसे पानी बचाने वाली फसल भी कहते हैं। ज्यादा बारिश होने से पहले खेत में जल निकासी का प्रबंध करें, ताकि पानी फसल में ना भर पाए। मूंगफली की फसल में पानी भरने से कीड़े और बीमारियां लगने की संभावना बढ़ जाती है। कम बारिश होने पर आवश्यकतानुसार सिंचाई बेहद जरूरी है।

जैविक कीटनाशकों का करें प्रयोग

मूंगफली की फसल में ज्यादा खरपतवार निकल आते हैं, जो पौधे की बढ़वार और उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसलिए, बुवाई के 15 दिन बाद और 35 दिन बाद खेतों में निराई-गुड़ाई करके खेत में उगने वाली घास को उखाड़े। फसल में कीटों और रोगों की निगरानी करते रहें। हर 15 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें।

एक हैक्टेयर में मुलेठी की खेती करके 4000 किलो तक उत्पादन

मुलेठी की खेती कर आप भी हो जाएंगे अमीर, बंजर जमीन भी फलदायक

भोपाल। जागत गांव हमार

हमारे देश में प्राचीन समय से ही औषधीय पौधों की खेती बड़े स्तर पर की जाती हैं। इन पौधों की खेती कर किसान भाई अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हैं। इनकी खेती करने से बंजर पड़ी जमीन का भी इस्तेमाल हो जाता है। ऐसे में मुलेठी की खेती कर शानदार लाभ हासिल कर सकते हैं। मुलेठी की जड़ से झाड़ी व मोटा तना बनने में करीब तीन वर्ष का समय लगता है। वहीं, कटाई के बाद 1 हैक्टेयर में मुलेठी की खेती करके 4000 किलो तक उत्पादन किया जा सकता है।

कई साल तक कर सकते हैं खेती- कटाई के बाद खेतों में मुलेठी की जड़ रह जाती है, जिसे सिंचाई करके फिर से उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। एक बार मुलेठी की खेती करके किसान कई सालों तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में मुलेठी की खेती का बहुत उपयोग होता है। मुलेठी को आयुर्वेदिक या अन्य दवा कंपनियां 50 से 100 रुपए के बीच खरीदती हैं। इससे किसानों को बंजर मिट्टी का सही इस्तेमाल करके कम लागत में अच्छी कमाई करने का अवसर मिलता है।

- खेत की मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए 2-3 गहरी जुताई करें।
- आखिरी जुताई से पहले खेत में दस से पंद्रह गाड़ी गोबर की सड़ी खाद, आठ किलो नाइट्रोजन और सोलह किलो फास्फोरस का मिश्रण मिला दें।
- खेतों में रोपाई से पहले जड़ों को सही तरह से तैयार कर लें। जो फसल में कीड़ों और बीमारियों को रोकता है।
- रोपाई करने से पहले, 8-9 इंच लंबे, दो या तीन आंखों वाले टुकड़ों को काटकर तीन या चार भाग को मिट्टी में दबा दें।
- कतारों में मुलेठी रोपें और रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें।
- पौधे की बढ़वार होने तक मिट्टी को पर्याप्त नमी में रखें।
- खेत में निराई-गुड़ाई करते रहें और खरपतवारों को देखते रहें।

सौंफ की खेती करा सकती है शनदार कमाई

इधर, सौंफ एक ऐसा मसाला है जो घरों से लेकर बड़े-बड़े होटलों तक इस्तेमाल में ली जाती है। सौंफ का उपयोग विभिन्न पकवान व औषधियों में इस्तेमाल होता है। बता दें कि केसर और वनिला की तरह सौंफ भी काफी महंगा मसाला है। सौंफ की खेती करने के लिए खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में अच्छा हैं। खरीफ के समय में सौंफ की बुवाई होती है। जबकि रबी के मौसम में इसकी बुवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते तक की जा सकती है।

जरूरी तापमान- किसान भाई मिट्टी पलटने के बाद 3 से 4 जुताई करके खेत को समतल बना लें। इसके आखिरी के जुताई के समय 150 से 200 कुंतल सड़ी गोबर की खाद मिला देनी चाहिए। इसके बाद खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें। सौंफ की अच्छी पैदावार के लिए 20 से लेकर 30 डिग्री का तापमान होना जरूरी है। समय के साथ ही सौंफ की मांग भी बढ़ी है।

इस तरह करें कटाई- किसान भाई सौंफ जब पूरी तरह तैयार हो जाए और बीज पूरी तरह जब पककर सूख जाए तब गुच्छों की कटाई करनी शुरू कर दें। सौंफ की कटाई करने के बाद एक दो दिन धूप में सुखा दें।

बड़वाह विकासखंड के 30 ग्राम, कसरावद के 37, महेश्वर के 22 तथा खरगोन के 15 ग्राम प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित

पशुधन के बचाव व स्वास्थ्य रक्षा के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

खरगोन। जागत गांव हमार

पशुधन के बचाव व स्वास्थ्य रक्षा के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित-प्रति वर्ष खरगोन जिले में बारिश से नर्मदा, कुंदा, वेदा, बाकुड़ व डालकी नदी से आने वाली बाढ़ से कई ग्राम प्रभावित होते हैं। इसमें बड़वाह विकासखण्ड के 30 ग्राम, कसरावद के 37, महेश्वर के 22 तथा खरगोन के 15 ग्राम प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जिले में अतिवृष्टि व प्राकृतिक आपदा की सक्रियता को देखते हुए संभावित बाढ़ से पशुधन के बचाव व उनके स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था के लिए विकासखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

संबंधित क्षेत्र के पशुपालक इनसे करें सम्पर्क - बडवाह क्षेत्र के लिए डॉ. सुरेश बघेल 975455-2558, डॉ. किशन सेप्टा 9424070725, कैलाश कार्यालय सहायक, सनावद क्षेत्र में डॉ राजेश प्रधान, आरएस बिरले 9826596365, राधेश्याम चौहान कार्यालय सहायक, कसरावद क्षेत्र के लिए डॉ. दिनेश वर्मा 8878564558, डॉ. ललीत पाटीदार 9425459680, आशिक खान 9826533184, रतनसिंह चौहान 8319148861, गोपाल बालके कार्यालय सहायक, खरगोन क्षेत्र के लिए डॉ खेमेन्द्र रोकड़े 8962783286, एलएल सोलंकी 9826229644, कार्यालय सहायक सोहन यादव,

महेश्वर क्षेत्र के लिए डॉ. महेश बर्मन 9340173331, डॉ. एल एस चौहान 9893403234, कमा कार्यालय सहायक, मंडलेश्वर क्षेत्र के लिए डॉ. बीएल पटेल 9026581511, सुभाष भुरिया, सहायक नरेन्द्र, धरगांव क्षेत्र में डॉ. जगवीर सिंह कनेश 9886387592, डॉ. आनंद पाटीदार 9340656830, अजुर्न मंडलोई 9093832819, सहायक बसंत वर्मा, भगवानपुरा क्षेत्र में डॉ। भाईसिंह डाबर 7223832240, अशोक भावसार 9826967431 तथा गोगांवा क्षेत्र के लिए डॉ। एनएस अखाड़े 9926045124, जीपी कुशवाह 9926089480 व एमसी यादव 9926952105 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने मुरैना-श्योपुर को किया ग्रीन ऐग प्रोजेक्ट में शामिल,116 गांवों का होगा विकास

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर की श्योपुर, मुरैना के किसानों को बड़ी सौगात

श्योपुर। प्रधान संपादक

पर्यावरण संरक्षण के साथ कृषि को व्यवहारिक और आसान तथा अधिक लाभ वाली बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ग्रीन ऐग प्रोजेक्ट को पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया है। जो देश के चार प्रदेशों में संचालित होगी। जिसमें मप्र का चयन चंबल संभाग के रूप में किया गया है। इस योजना के तहत चंबल संभाग में आने वाले श्योपुर और मुरैना जिले को शामिल करते हुए 98 हजार हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा जिसके दायरे में 116 गांव आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार योजना बनाकर इस क्षेत्र में वन, कृषि, सहकारिता, जल सहित इत्यादि का संरक्षण कर योजना को अमलीजामा पहनाएगा। देश के पांच प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुए इस अभियान में मप्र के श्योपुर मुरैना संसदीय क्षेत्र को जुड़वाने में केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इन दोनो जिलों की दशा और दिशा बदलना तय माना जा रहा है।

ग्रीन-ऐग परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, 'कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग' इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है।इस परियोजना को खाद्य एवं कृषि संगठन तथा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य, भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा

ग्रीन-एजी परियोजना के लक्ष्य

पांचो भू-प्रदेशों की कम से कम 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि में मिश्रित भूमि-उपयोग पद्धतियों से विभिन्न वैश्विक पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करना और कम से कम 104,070 हेक्टेयर कृषि-भूमि को सतत भूमि और जल प्रबंधन के अंतर्गत लाना भी रहेगा कृषि पद्धतियों के उपयोग से 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का पृथकीकरण सुनिश्चित करना यानी पर्यावरण सुरक्षा करना शामिल है चूंकि इस प्रोजेक्ट में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को राष्ट्रीय क्रियान्वयन एजेंसी बनाया है और वन विभाग, जल संसाधन विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है जिसके तहत इस वेल्ट में आने वाले गांव कृषि क्षेत्र, वन्य क्षेत्र एवं वन्यजीवों से जुड़े क्षेत्र, जलीय क्षेत्र एवं जलीय जीवों से जुड़े क्षेत्रों की चिंता और उनका सामूहिक संरक्षण भी किया जाएगा। योजना के तहत क्षेत्र की सभी नदियों और संभावित जल प्रवाहित वाले क्षेत्रों को जोडकर शत प्रतिशत चिंहित जमीन को सिंचाईयुक्त बनाया जाएगा।

पद्धतियों को एकीकृत करना है। यह पायलट परियोजना सभी राज्यों में 31 मार्च, 2026 तक जारी रहेगी। इस परियोजना के अंतर्गत, राज्य के 35 गांवों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसमें दो संरक्षित क्षेत्रों डंपा बाघ अभयारण्य तथा थोरंगटलांग वन्यजीव अभयारण्य को भी सम्मिलित किया गया था अब चंबल के साथ कूनो नेशनल सेंचुरी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की कवायद चल रही है।

सब्जी करी फसल को रोगों से बचाव के बताए उपाय

भोपाल। धान की फसल के साथ-साथ सब्जियों की खेती के लिए ये समय बहुत संवेदनशील है। इस वक्त सब्जियों की फसल में कई तरह के रोग लग रहे हैं। इससे किसानों की पैदावार कम हो रही है। पैदावार कम होने के चलते उनकी आमदनी में कमी दर्ज की जा रही है।

टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी व पत्तागोभी की फसल का बचाव- टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी व पत्तागोभी में फल छेदक, शीर्ष छेदक लगता है। इसकी निगरानी के लिए फिरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। प्रति एकड़ 3-4 ट्रैप का इस्तेमाल हो तो अच्छा है। प्रकोप अधिक दिखाई दे तो स्पेनोसेड़ 1.0 मिली प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी व पत्तागोभी के अलावा भिंडी, मिर्च और बैंगन की फसल में माइट, जैसिड और होपर जैसे रोगों का खतरा बढ़ गया। इन फसलों से कीटों की रोकथाम के लिए लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल

कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बरतन में पानी और थोड़ा कीटनाशक मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रखे दें। लाइट से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे।

अगेती मटर और सरसों की साग की ऐसे करें देखभाल

किसान इस समय अगेती मटर की बुवाई के लिए बीज की व्यवस्था कर रहे हैं। इसकी उन्नत किस्में-पूसा प्रगति, पंत मटर-3 और आर्किल हैं। इसके लिए खेतों को पहले से तैयार कर लें। इस मौसम में किसान गाजर की बुवाई मेड़ों पर कर सकते हैं। इसकी उन्नत किस्म पूसा रूधिरा है। बीज दर 4.0 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। बुवाई से पहले बीज को केप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। खेत में देसी खाद, पोटाश और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। अंकुरण के लिए मिट्टी में उचित नमी का होना आवश्यक है। वहीं, सरसों की साग की बेहतर विकास के लिए उसकी बुवाई कर उथली क्यारियों पर करें।

बाएफ किसान मार्ट-दुग्ध संकलन केंद्र शुरू दूध से बने उत्पादों की मार्केटिंग के सुझाव

विदिशा। जागत गांव हमार

विदिशा विकासखंड के ग्राम सलैया में नाबार्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित करीला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड खेजड़ा सुल्तान के द्वारा ग्राम सलैया में बाएफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन का किसान मार्ट और दुग्ध संकलन केंद्र का शुभारंभ बायफ बीआईएसएलडी संस्था के एडवाइजरी बोर्ड सदस्य शंकर लाल, रमेश सामा के द्वारा किया गया।

इस अवसर पर नाबार्ड की एजीएम जगप्रीत कौर लीड बैंक प्रबंधक नरेश मेघानी, मुख्य प्रबंधक एसबीआई शाखा भोपाल व्ही एस बघेल, शाखा प्रबंधक एसबीआई खामखेड़ा प्रवीण दिसोरिया, बीआईएसएलडी संस्था के एडवाइजरी बोर्ड सदस्य एवं रीजनल डायरेक्टर वेस्ट रीजन वाई बी दियासा, डॉ जयंत खड़से कार्यक्रम निदेशक महाराष्ट्र, वामन कुलकर्णी सीटीपीई एनआरएम, जयंत मोरी कार्यक्रम निदेशक गुजरात, पवन पाटीदार राज्य प्रमुख मप्र, अभिषेक पांडेय राज्य प्रमुख गुजरात, कमलेश कुमार मौजूद थे।

बायफ किसान मार्ट के शुभारंभ के पश्चात महिला डेयरी उद्यमियों के साथ परिचर्चा का आयोजन किया गया। उक्त परिचर्चा में डेयरी व्यवसाय से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ कैसे लिया जा सकता है के बारे में बोर्ड सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए। सभी बोर्ड सदस्यों तथा बैंक अधिकारियों के द्वारा करीला किसान उत्पादक कंपनी लि। के कार्यालय खामखेड़ा में सभी बोर्ड सदस्यों के साथ चर्चा की गई तथा कंपनी का टर्न ओवर एक करोड़ तक करने के लिये अधिक से अधिक दूध संकलित कर दूध से बने उत्पादों की मार्केटिंग करने के सुझाव दिए गए।

ज्वार और बाजरा के पंजीयन कार्य 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा

भोपाल। जागत गांव हमार

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा उपार्जन हेतु किसान पंजीयन कार्य 20 सितंबर से प्रारंभ होकर 5 अक्टूबर तक किया जायेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 समर्थन मूल्य ज्वार-3180 रुपये एवं बाजरा-2500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित हैं। किसान पंजीयन के लिए सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं के खोले गए कुल 13 पंजीयन केन्द्र, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर समस्त कार्य दिवसों में (रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर) नि:शुल्क पंजीयन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर 50 रुपये राशि का भुगतान कर सशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे से पंजीयन कार्य करने हेतु आवेदन इच्छुक संचालनकर्ता को ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन आवश्यक दस्तावेज सहित ऑनलाइन दर्ज करना होगा। ऐसे पंजीयन केन्द्र का सत्यापन उपरांत ही किसान पंजीयन का कार्य कर सकेंगे। उन्होंने सभी किसानों से अनुरोध किया कि वे समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए अपना पंजीयन नज़दीकी पंजीयन केन्द्र पर उपस्थित होकर कराएं।

-सबसे ज्यादा नरसिंहपुर में, सबसे कम अशोकनगर-सतना में बारिश

रिकॉर्ड बारिश से मध्यप्रदेश सूखे से बाहर, 22 जिलों का कोटा फुल

भोपाल । जागत गांव हमार

सितंबर महीने में हुई रिकॉर्ड बारिश से मध्यप्रदेश में सूखे का संकट खत्म हो गया है। 15 दिन पहले तक प्रदेश में सामान्य से 23 फीसदी तक बारिश कम हुई थी, लेकिन इसके बाद ऐसी झड़ी लगी कि अब यह 1 फीसदी भी नहीं बची है। इंदौर, उज्जैन समेत 22 जिले रेड जोन यानी सूखे की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। इंदौर संभाग के सभी 8 जिलों में आंकड़ा 100 फीसदी के पार है, जबकि अगस्त तक इन जिलों में कोटे की आधी बारिश भी नहीं हुई थी। जबलपुर-सीहोर समेत 13 जिले ऐसे हैं, जहां 99 फीसदी तक बारिश हो चुकी है। प्रदेश में अब तक औसत 36.57 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि औसत 36.68 इंच बारिश होनी चाहिए थी। इस हिसाब से आधा इंच से भी कम बारिश बची है। ओवरऑल बात करें, तो प्रदेश में 0.3 फीसदी बारिश कम हुई है। इनमें पूर्वी हिस्से में औसत से 4 फीसदी कम, जबकि पश्चिमी हिस्से में आंकड़ा औसत से 3 फीसदी अधिक है। सितंबर की औसत बारिश 6 इंच है। इसके मुकाबले साढ़े 10 इंच बारिश अब तक हो चुकी है। सीनियर वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह ने बताया कि सितंबर में बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुए। दूसरे सप्ताह में तेज बारिश हुई। ब्रेक के बाद 22 सितंबर से फिर तेज बारिश शुरू हो गई। इससे जो जिले रेड जोन में थे, वे बाहर निकल आए।

दो महीने बेरुखी

इस साल मानसून ने प्रदेश में 24 जून को एंट्री की थी। शुरुआत में अच्छी बारिश हुई, लेकिन जुलाई और फिर अगस्त में मानसून ने बेरुखी दिखाई। इसके चलते बारिश का आंकड़ा कम रहा। सितंबर में मानसून के स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गए। इस कारण तेज बारिश हुई।

नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा

प्रदेश में सबसे ज्यादा वाले जिले की बात करें, तो वह नरसिंहपुर है। यहां अब तक 51.18 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि यहां की सामान्य बारिश 41.40 इंच है। इस हिसाब से यहां 123 फीसदी बारिश हो चुकी है। इंदौर में करीब 50 इंच बारिश हो गई है। संभाग के बुरहानपुर में सामान्य बारिश 29.01 इंच की तुलना में 42.41 इंच बारिश हो चुकी है, जो 146 फीसदी से ज्यादा है। धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा और खरगोन में भी कोटा फुल हो गया है।

यहां 40 इंच से ज्यादा बारिश

जबलपुर, रायसेन, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, निवाड़ी, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल और अनूपपुर में बारिश का आंकड़ा 40 इंच से ज्यादा है। भिंड में सामान्य बारिश का आंकड़ा 141 फीसदी तक पहुंच गया है। भिंड की सामान्य बारिश 24.11 इंच है, जो अन्य जिलों के मुकाबले काफी कम है। यहां अब तक 34.04 इंच बारिश हो चुकी है। अशोकनगर में सबसे कम 22.93 इंच पानी गिरा है, जबकि सतना में 23.19 इंच बारिश हुई है।

15 दिन में बदली तस्वीर

9-10 सितंबर तक प्रदेश के 23 जिले रेड जोन में थे। इनमें भोपाल, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, आलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, शाजापुर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, बालाघाट, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले शामिल थे। इसके बाद तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। 17 जिले रेड जोन से बाहर निकल आए। वर्तमान में गुना, अशोकनगर, दमोह, सतना, रीवा और सीधी ही रेड जोन में हैं। यहां 23 फीसदी से 37 फीसदी तक कम बारिश हुई है।

आसरा के बाद क्वारंटाइन सेंटर भी फुल, तीन दिन से ननि नहीं उठा रहा संक्रमित पशु

गांधी नगर में क्वारंटाइन सेंटर में भी नहीं बची जगह

अब तक लंपी से 25 गोवंश की मौत, 222 संक्रमित

भोपाल।

लंपी वायरस का संक्रमण शहर में बेकाबू हो चुका है। आलम यह है कि जहांगीराबाद स्थित पशु आश्रय स्थल आसरा के बाद अब गांधी नगर में क्वारंटाइन सेंटर में भी जगह नहीं बची है। इस कारण तीन दिन से नगर निगम का अमला लंपी संक्रमित गोवंश को उठा ही नहीं रहा है। ये हालात तब हैं जब कॉल सेंटर पर रोजाना 4 से 6 शिकायतें लंपी संक्रमित गोवंश की पहुंच रही हैं। नगर निगम के अमले की ओर से हाथ खड़े करने के कारण लंपी संक्रमित गोवंश जहां-तहां तड़पते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है कि अगर शहर में कहीं किसी को लंपी वायरस के लक्षणों वाला गोवंश नजर आए तो नगर निगम के कॉल सेंटर नंबर 155304 और 18002330014 पर कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं। नगर निगम की गोवर्धन परियोजना से गाड़ी भेजकर उक्त गोवंश को लाकर इनका इलाज किया जाएगा। लेकिन नगर निगम का अमला गोवंश नहीं उठा रहा है। कॉल सेंटर पर दर्ज शिकायत के संबंध में कॉल सेंटर से शिकायतकर्ता को कॉल करके कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर फुल होने के कारण हम गोवंश को उठाकर उसका इलाज कराने में असमर्थ हैं।

सेंटर के लिए देख रहे जगह- निगम अधिकारियों का कहना है कि पहले आसरा में लंपी संक्रमित गोवंश को रखकर इलाज करा रहे थे। उसके फुल होने के बाद गांधी नगर के कांजी हाउस को क्वारंटाइन सेंटर बनाया पर वह भी फुल हो गया है। अब नए क्वारंटाइन सेंटर के लिए जगह देख रहे हैं।

मंत्री ने डांटा तो सक्रिय हुए- निगम की गोवर्धन शाखा में अफरा-तफरी मची हुई थी। कर्मचारियों की मानें तो मंत्री स्टाफ में शामिल कोई अधिकारी आकृति इको सिटी सलैया तरफ रहते हैं। उन्होंने नगर निगम को लंपी संक्रमित गाय उठाने के लिए कॉल किया था। उन्हें भी जवाब दिया गया कि क्वारंटाइन सेंटर फुल है। इसके बाद मंत्री ने अफसरों को फटकार लगाई तो सारा अमला गोवंश की तलाश में जुट गया।

25 में से 18 मौतें आसरा में

अकेले आसरा में 27 अगस्त से अब तक 48 लंपी संक्रमित गोवंश को लाया गया। इनमें से 30 गोवंश ही बचे हैं। स्टाफ ने बताया कि जो भी लंपी संक्रमित गोवंश आए हैं, उनको शेड सी में रखा गया है। एक भी गोवंश को न तो रिलीज किया है और न कहीं और ही भेजा है। जिन गोवंश की मौत हुई वे शेड से बाहर गए हैं। ऐसे में यहां 25 गोवंश की मौत हो चुकी है। 4 गोवंश की मौत पशु पालकों के पास हुई है।

- एक बछड़े को लंपी के लक्षण हैं। उसकी सूचना कॉल सेंटर पर दी थी। शनिवार सुबह फोन आया कि पकड़ने आ रहे हैं, पर नहीं आए। दोपहर में कॉल सेंटर से बताया कि क्वारेंटाइन सेंटर फुल है, गाड़ी नहीं आएगी।

-विशाल सिंह, नयापुरा कोलार

- गांधी नगर के कांजी हाउस को क्वारेंटाइन सेंटर बनाया है, इसकी क्षमता 40 गोवंश की है, जो फुल हो चुका है। नई शिकायतें आ रही हैं, उन गोवंश को हम नहीं उठा पा रहे हैं।

-विनय सोनी, सुपरवाइजर, गोवर्धन परियोजना

- आसरा और क्वारेंटाइन सेंटर फुल हो चुके हैं। हम क्वारेंटाइन सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। व्यवस्था कर ली जाएगी।

-डॉ. अजय रामटेके, उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं

पशु एंबुलेंस पर 48 घंटे की वेटिंग

सरकार की ओर से चलाई जा रही पशु एंबुलेंस 1962 पर रोज 25-30 कॉल पहुंच रहे हैं। एंबुलेंस स्टाफ की मानें तो जिले में 3 गाड़ियां हैं। भोपाल शहर, फंदा और बैरसिया ब्लॉक के लिए एक-एक गाड़ी है। ऐसे में शहरभर से आ रही शिकायतों पर जाने का जिम्मा एक ही गाड़ी पर है। यही वजह है कि 48 घंटे तक की वेटिंग चल रही है। एक बार गाड़ी बुलाने पर 150 रुपए चार्ज देना होता है। फॉलोअप के लिए दोबारा चार्ज देना पड़ता है।

गायों को लगने वाले इंजेक्शन में फंगस

दवाओं के कंपाउंड गलत.. डॉक्टरों ने बंद किया इस्तेमाल

इधर, लंपी संक्रमण के बीच पशुपालन विभाग गायों और मवेशियों के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन के वायल में फंगस जैसे सफेद कण नजर आ रहे हैं। टैबलेट्स के एक बैच में 10 गोलियों की पैक स्ट्रिप में एक भी टैबलेट नहीं है। कई अन्य दवाओं के कंपाउंड गलत हैं। ऐसे में कई वेटरनरी डॉक्टरों ने ये दवाएं लिखना बंद कर दिया है। हाल ही में विभागीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने इन दवाओं की क्वालिटी पर सवाल उठाए गए। लेकिन अधिकारियों ने अधीनस्थों को विभाग की छवि न खराब करने की बात कहकर चुप करा दिया। दैनिक भास्कर ने इस संबंध में सवाल पूछा तो संचालक पशुपालन ने ऐसी शिकायत नहीं मिलने की बात कही।

दवा या जहर...

एनरोफ्लोक्सोसिन के वायल में फंगस और कचरा जमा दिख रहा है। वायल के बेस में ही कचरे के छोटे-छोटे कण साफ नजर आते हैं। पशुओं की कृमिनाशक दवा में स्पेलिंग गलत लिखी है। एमोक्सिसिलिन और जेंटामाइसिन कंपाउंड की एंटोबायोटिक है। डॉक्टरों का कहना है कि यह गलत है, क्योंकि एमोक्सीसिलिन पाउडर फार्म है और जेंटामाइसिन तरल। एक साथ नहीं दे सकते हैं।

दूध पर पड़ेगा असर

एक अन्य कृमिनाशक क्लोसेनटेल दी गई है। इसके वॉयल पर एक्टरनल यूज ओनली लिखा हुआ है। यह भी गलत है, क्योंकि क्लोसेनटेल का उपयोग ओरली किया जाता है। आइवरमेक्टिन ट्यूब पर इंट्रामेमरी लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अंदर दिया जाना है, जबकि यह थन के अंदर नहीं दिया जाता है। अगर इस दवा को गाय के थन में लगाएंगे तो सीधा असर दूध पर पड़ सकता है।

- एसोसिएशन के एमपी चेप्टर से मुझे जानकारी मिली है कि दवाओं की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सरकारी डॉक्टर्स ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

-डॉ. चितरंजन कादयान, अध्यक्ष, इंडियन वेटरनरी एसो.

- अगर किसी दवा या इंजेक्शन में कोई समस्या है तो संबंधित अधिकारी बताएं। जिसने भी सप्लाई की होगी, उस कंपनी से स्पष्टीकरण लेंगे। वैसे तो शिकायत नहीं आई पर किसी बैच में ऐसी समस्या है तो उसकी भी जांच करवाएंगे।

-डॉ. आरके मेहिया, संचालक, पशुपालन विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए गेम-चेंजिंग पहल का अनावरण किया

कृषि में क्रांतिकारी बदलाव

निर्मला और तोमर ने किया केसीसी घर-घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और विंड्स मैनुअल का अनावरण

- चावल -गेहूं के उत्पादन के लिए सही समय अनुमान की सराहना
- अनुमान को दलहन-तिलहन फसलों तक बढ़ाने का आह्वान किया
- कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता सबसे अहम

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कृषि-ऋण और फसल बीमा पर केंद्रित पहल का अनावरण किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने तीन पहलें शुरू कीं, किसान ऋण पोर्टल (केआरपी), मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम पर मैनुअल, केसीसी घर-घर अभियान, एक महत्वाकांक्षी अभियान जिसका लक्ष्य देश भर के प्रत्येक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पहुंचाना है। इन पहलों का उद्देश्य कृषि में क्रांति लाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डेटा उपयोग को अनुकूलित करना और देशभर में किसानों के जीवन में सुधार करना है।

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घर-घर केसीसी अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों को आसान अल्पकालिक ऋण सुनिश्चित करने और इस योजना से जुड़ने के लिए केसीसी योजना के तहत पर्याप्त धन आवंटित किया है। वित्त मंत्री ने पीएम फसल बीमा योजना की पहल और सफल कार्यान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों को 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रीमियम राशि के मुकाबले 1,40,000 करोड़ बीमा राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने चावल और गेहूं की फसल के उत्पादन के वास्तविक समय के अनुमान की भी सराहना की और इस अनुमान को दलहन और तिलहन की फसलों तक बढ़ाने का आह्वान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि फसलों के वास्तविक समय आकलन से अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी और फसल सीजन के अंत में किसानों के लिए सही कीमतें सुनिश्चित होंगी।

सीतारमण ने घर-घर केसीसी अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया

विंड्स मैनुअल का उद्देश्य वास्तविक समय की मौसम की जानकारी सुनिश्चित करना

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि मंत्रालय का बजट वर्ष 2013-14 में 23,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। विंड्स मैनुअल के बारे में बात करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वास्तविक समय की मौसम की जानकारी सुनिश्चित करना है ताकि किसान सही समय पर अपनी फसलों के लिए सावधानी बरत सकें। कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और इस सरकार ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9 करोड़ लाभार्थी हैं और केसीसी घर-घर अभियान का उद्देश्य 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ना है जो अभी तक केसीसी योजना से नहीं जुड़े हैं। तोमर ने कोरोना महामारी के दौरान भी किसानों को लगभग 2 करोड़ केसीसी प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय और बैंकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह कृषि और ग्रामीण क्षेत्र ही था जिसने कोरोना महामारी के दौरान भी अर्थव्यवस्था को चालू रखा।

किसान ऋण पोर्टल

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग और नाबार्ड द्वारा सहयोगपूर्वक विकसित, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सेवाओं तक पहुंच में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह किसानों को संशोधित ब्याज अनुदान योजना के माध्यम से रियायती कृषि ऋण प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। कृषि ऋण पोर्टल एक एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो किसान डेटा, ऋण वितरण की विशिष्टताओं, ब्याज अनुदान के दावों और योजना उपयोग की प्रगति का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

घर-घर केसीसी अभियान

घर-घर के सी सी अभियान की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह अभियान सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक किसान के पासङ्ग बिना किसी बाधा के क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच हो जो उनकी कृषि गतिविधियों को चलाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मौजूदा केसीसी खाताधारकों के डेटा को पी एम किसान डेटाबेस के साथ सावधानी पूर्वक सत्यापित किया है, उन खाताधारकों की पहचान की है जो पीएम किसान डेटाबेस से मेल खाते हैं और जो पीएम किसान लाभार्थी होने के बावजूद के सी सी खाते नहीं रखते हैं।

विंड्स मैनुअल का शुभारंभ

मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (विंड्स) पहल तालुक/ ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन और वर्षामापी का नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक अग्रणी प्रयास है। यह पहल मौसम डेटा का एक मजबूत डेटाबेस बनाता है, जो विभिन्न कृषि सेवाओं का समर्थन करता है। विंड्स मैनुअल हितधारकों को पोर्टल की कार्यक्षमताओं, डेटा व्याख्या और प्रभावी उपयोग की गहन समझ प्रदान करता है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विंड्स प्लेटफॉर्म के साथ स्थापित करने और एकीकृत करने में मार्गदर्शन करता है, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ डेटा अवलोकन और संचरण को बढ़ावा देता है।

नपा की गौशाला में चौहद गायों की मौत
शिवपुरी में अव्यवस्था के कारण तोड़ा दम

शिवपुरी। शिवपुरी नगर पालिका द्वारा संचालित एक गौशाला में 14 गायों की मौत हो गई है। नगर पालिका परिषद शिवपुरी द्वारा संचालित लुधावली गौशाला में एक ही रात में 14 गायों की मौत हो गई। गायों के मरने की खबर के बाद गौसेवकों में नाराजगी है। यहां पर गौशाला का संचालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। सही देखरेख न होने और चारे की कमी के चलते यहां पर गायों की मौत हुई। पहले यहां पर इस गौशाला का संचालन एक सामाजिक संस्था द्वारा किया जाता था। लेकिन नगर पालिका ने मनमानी करते हुए स्वयं व्यवस्था हाथ में ले ली। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पहले समाज सेवी संस्था इसकी अच्छी तरह से संचालन करती थी। लेकिन नगर पालिका के कुछ कार्यकर्ताओं को यह अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद मनमाने ढंग से गौशाला खुद नगर पालिका चलाने लगी। लेकिन धीरे-धीरे यहां की व्यवस्थाएं बिगड़ती चली गईं।

राजनीति भी गरमाई

जिस लुधावली गौशाला में गायों की मौत हुई है। वह भाजपा शासित नगर पालिका द्वारा संचालित की जाती है। शिवपुरी नपा में भाजपा नेत्री गायत्री शर्मा नगर पालिका अध्यक्ष हैं और इनकी नगर पालिका द्वारा ही यहां पर इस गौशाला का संचालन किया जाता है। इन गायों की मौत के बाद भाजपा से इस्तीफा देने वाले और कांग्रेस में गए नेता कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस पर निशाना साधते हुए कहा है कि गायों की मौत की जांच होना चाहिए। विधायक रघुवंशी ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। वीरेंद्र रघुवंशी ने गौशाला में गायों की मौत के मामले में कलेक्टर से अपील की है कि यहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। गायों की मौत पर कांग्रेस ही नहीं भाजपा के नेता भी नाराज हैं। शिवपुरी नगर पालिका उपाध्यक्ष पति और सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास ने इस घटना को दुखद बताया है कि रामजी व्यास का कहना कि गोशाला में पूर्व में भी गोवंश की मौतें हो चुकी है लेकिन कोई सबब नहीं लिया गया। रामजी व्यास ने कहा इसकी जांच होना चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)